सूचकांक एवं रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018 (International IP Index, 2018)

- 8 फरवरी, 2018 को यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा 6वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018 (International IP Index, 2018) का प्रकाशन किया गया।
- इस वर्ष के सूचकांक की थीम- 'सृजन' (Create) है।
- इस सूचकांक को बनाने के लिए 40 संकेतकों को 8 श्रेणियों में बांटा गया और देशों द्वारा प्रत्येक श्रेणी में अर्जित अंकों के आधार पर मुख्य सूचकांक को बनाया गया है।
- इस सूचकांक में 50 देशों को शामिल किया गया है, जबकि गतवर्ष इस सूचकांक में 45 देश थे।
- इस वर्ष सूचकांक में पांच नए देशों (अर्थव्यवस्थाओं)– कोस्टारिका, आयरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को और नीदरलैंड्स को शामिल किया गया है।

प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले देश एवं उनके अंक-

1. यूएसए-37.98
2. यूके-37.97
3. स्वीडन-30.99
4. फ्रांस- 36.74
5. जर्मनी-36.54
6. आयरलैंड-35.98
7. नीदरलैंड्स-35.33
8. जापान-34.58
9. सिंगापुर-33.45
10. स्विट्जरलैंड-33.42

अंतिम पांच स्थान प्राप्त करने वाले देश एवं उनके अंक-

50. वेनेजुएला-6.85
49. अल्जीरिया-9.53
48. मिस्र -10.10
47. पाकिस्तान-10.41
46. अर्जेंटीना-11.55

- अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018 में भारत 12.03 अंकों के साथ 44वें स्थान पर है।
- जबकि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 43वें स्थान पर था।
- ब्रिक्स देशों में चीन 25वें, रूस-29 वें, ब्राजील-33 वें तथा द. अफ्रीका 39 वें स्थान पर है।

बौद्धिक संपदा क्या है?

- किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। व्यक्ति अथवा संस्था को अपनी इन कृतियों पर प्राप्त अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्ति या संस्था को अपनी रचना/आविष्कार पर एक निश्चित अवधि के लिए विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।
- इन विशेष अधिकारों का विधि द्वारा संरक्षण पेटेंट, कॉपीराइट अथवा ट्रेडमार्क आदि के रूप में किया जाता है। इससे सर्जक खोज तथा नवाचार के लिए उत्साहित और उद्यत रहते हैं और वित्तीय एवं वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक अमेरिका वाणिज्यिक संगठन यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित 'ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर' द्वारा दिसंबर, 2012 से जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण तथा इसके मानदंडो का बचाव और संवर्धन करना है।

समावेशी सूचकांक -2018

- 22 जनवरी, 2018 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा समावेशी विकास सूचकांक (The Inclusive Development Index)-2018 जारी किया गया।
- इस सूचकांक में विश्व की 103 अर्थव्यवस्थाओं (देशों) को शामिल किया गया है।

- सूचकांक में 29 विकसित एवं 74 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
- समावेशी विकास सूचकांक-2018 में 29 विकसित अर्थव्यवस्थाओं (Advanced Economics) में नॉर्वे (स्कोर-6.08) शीर्ष स्थान पर रहा।
- इसके पश्चात आइसलैंड (स्कोर-6.07) दूसरे, लक्जमबर्ग (स्कोर-6.07) तीसरे, स्विट्जरलैंड (स्कोर-6.05) चौथे तथा डेनमार्क (स्कोर-5.81) पांचवें स्थान पर है।
- अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऑस्ट्रेलिया 9वें, जर्मनी 12वें, कनाडा 17वें, फ्रांस 18वें, यूनाइटेड किंगडम 21वें, अमेरिका 23वें तथा जापान 24वें स्थान पर है।
- इस सूचकांक में 74 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (Development Economics) में लिथुआनिया (स्कोर-4.86) शीर्ष पर रहा।
- इसके पश्चात हंगरी (स्कोर-4.74) दूसरे, अजरबैजान (स्कोर-4.69) तीसरे, लाटविया (स्कोर-4.61) चौथे तथा पोलैंड (स्कोर-4.67) पांचवें स्थान पर है।
- समावेशी विकास सूचकांक (IDI) में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत (स्कोर-3.09) को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- जबकि गतवर्ष भारत को 60वां स्थान प्राप्त हुआ था।
- भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 22वें, बांग्लादेश 34वें, श्रीलंका 40वें तथा पाकिस्तान 47वें स्थान पर है।
- अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक्स देशों में रूस 19वें, चीन 26वें, ब्राजील 37वें तथा दक्षिण अफ्रीका 69वें स्थान पर है।

'वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक' (Global Talent Competitiveness Index)

- 22 जनवरी, 2018 को 'वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक' (Global Talent Competitiveness Index)-2018 का प्रकाशन दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया।
- इस सूचकांक का प्रकाशन 'इनसीड' (INSEAD) बिजनेस स्कूल द्वारा एडिको ग्रुप (Adecco Group) और टाटा कम्युनिकेशंस के सहयोग से किया गया।
- इस वर्ष के सूचकांक का विषय (Theme) (Diversity for Competitiveness) था।
- इस सूचकांक में 119 देशों को शामिल किया गया है।
- इस सूचंकाक में शीर्ष पांच स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं- 1. स्विट्जरलैंड, 2. सिंगापुर, 3. अमेरिका, 4. नार्वे तथा 5. स्वीडन।

इस सूचकांक में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं-

- 119-यमन, 118- मेडागास्कर, 117-मोजांबिक, 116-नेपाल तथा 115-जिम्बाब्वे।
- इस सूचकांक में भारत 81वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- जबकि गतवर्ष भारत 92वें पायदान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 82वां, भूटान को 91वां, पाकिस्तान को 109 वां तथा बांग्लादेश को 114वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- ब्रिक्स देशों में चीन 43वें, रूस 53वें, दक्षिण अफ्रीका 63वें तथा ब्राजील 73वें स्थान पर रहे।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स -2017

- 12 अक्टूबर, 2017 को अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) द्वारा 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2017' (Global Hunger Index-2017) जारी किया गया।
- GHI-2017 रिपोर्ट का मुख्य विषय (Theme) 'भूख से असमानताएं' (The Inequalities of Hunger) है।
- यह सूचकांक चार संकेतकों- 'अल्पपोषण' (Undernourishment), 'लंबाई के अनुपात में कम वजन' (Child Wasting), आयु के अनुपात में कम लंबाई (Child Stunting) तथा बाल मृत्यु दर (Child Mortality) के आधार पर तैयार किया गया है।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है जिसमें शून्य सबसे अच्छा स्कोर तथा 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है।
- GHI-2017 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से 2017 तक वैश्विक भुखमरी की स्थिति में 27 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 119 देशों को शामिल किया गया है।
- जिसमें से 44 देश अभी भी गंभीर अथवा भयावह स्थिति में हैं।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2017 में 5 से कम स्कोर वाले 14 देश हैं।
- जिसमें पांच शीर्ष देश क्रमशः बेलारूस, बोस्निया और हेरजेगोविना (संयुक्त रूप से), चिली, क्रोएशिया तथा क्यूबा हैं।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2017 में भारत जिबूती और रवांडा के साथ संयुक्त रूप से 100वें स्थान पर है जबकि गतवर्ष (2016) में 97वां (118 देशों) स्थान था।
- GHI-2017 में भारत का स्कोर-31.4 है।

- भारत अभी भी गंभीर (Serious) स्थिति में बना हुआ है।
- गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत की स्थिति पाकिस्तान (106वां स्थान) से बेहतर है।
- जबकि नेपाल (72वां स्थान), श्रीलंका (84वां स्थान), बांग्लादेश (88वां स्थान से खराब स्थिति में है।

क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स

- अलग-अलग देशों में लोगों को खाने की चीजें कैसी और कितनी मिलती हैं, यह उसे दिखाने का साधन है। 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' का सूचकांक हर साल ताजा आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। इस सूचकांक के जरिए विश्व भर में भूख के खिलाफ चल रहे अभियान की उपलब्धियां और नाकामियों को दर्शाया जाता है।
- 'ग्लोबल इंडेक्स स्कोर' ज्यादा होने का मतलब है, उस देश में भूख की समस्या अधिक है। उसी तरह किसी देश का स्कोर अगर कम होता है तो उसका मतलब है कि वहां स्थिति बेहतर है। इसे नापने के चार मुख्य पैमाने हैं- कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index), 2017

- 21 फरवरी, 2018 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 23वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index), 2017 जारी किया गया।
- इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों/क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है।
- यह सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तारित है जिसमें 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट (Highly Corrupt) तथा 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार (Very Clean) है।
- इस वर्ष सूचकांक में न्यूजीलैंड (स्कोर-89) शीर्ष स्थान पर है।
- इसके पश्चात डेनमार्क (स्कोर-88) दूसरे, फिनलैंड (स्कोर-85), नॉर्वे (स्कोर-85) एवं स्विट्जरलैंड (स्कोर-85) संयुक्त रूप से तीसरे तथा सिंगापुर (स्कोर-84) एवं स्वीडन (स्कोर-84) संयुक्त रूप से छठवें स्थान पर हैं।
- इस सूचकांक में सोमालिया (स्कोर-9) 180वें स्थान पर है अर्थात यह सर्वाधिक भ्रष्ट देश है।
- इसके पश्चात दक्षिण सूडान (स्कोर-12) 179वें, सीरिया (स्कोर-14) 178वें, अफगानिस्तान (स्कोर-15) 177वें, यमन (स्कोर-16) एवं सूडान (स्कोर-16) संयुक्त रूप से 175वें स्थान पर रहे।
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI)-2017 में भारत, घाना, मोरक्को तथा तुर्की (Turkey) के साथ संयुक्त रूप से 81वें स्थान पर है। इन सभी 4 देशों का सूचकांक स्कोर-40 है।
- जबकि गत वर्ष के सूचकांक में भारत 40 अंक के स्कोर के साथ बेलारूस, ब्राजील एवं चीन के साथ संयुक्त रूप से 79वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में भूटान (स्कोर-67) 26वें, चीन (स्कोर-41) 77वें, श्रीलंका (स्कोर-38) 91वें, पाकिस्तान (स्कोर-32) 117वें, नेपाल (स्कोर-31) 122वें तथा बांग्लादेश (स्कोर-28) 143वें स्थान पर हैं।
- इस सूचकांक में विश्व के अन्य विकसित देशों में यूनाइटेड किंगडम (UK) (स्कोर-82) 8वें, जर्मनी (स्कोर-81) 12वें, अमेरिका (स्कोर-75) 16वें, तथा जापान (स्कोर-73) 20वें स्थान पर है।
- ज्ञातव्य है कि यह सूचकांक वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था है जो भ्रष्टाचार निवारण आदि पर जोर देती है।
- इसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है।

'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट -2018'

- 31 अक्टूबर, 2017 को अमेरिका के वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा 15वीं रिपोर्ट 'डूइंग बिजनेस-2018' (Doing Business-2018) जारी किया गया।
- इस वर्ष की रिपोर्ट का केंद्रीय विषय (Theme) 'रोजगार सृजन में सुधार' (Reforming to Create Jobs) है।
- वर्ष-2018 हेतु जारी रिपोर्ट में 190 देशों की अर्थव्यवस्था को सम्मिलित किया गया है।
- डूइंग बिजनेस इंडेक्स-2018 की रिपोर्ट में 86.55 स्कोर के साथ न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

- इसके पश्चात सिंगापुर (स्कोर-84.57) को दूसरा, डेनमार्क (स्कोर-84.06) को तीसरा, कोरिया गणराज्य (स्कोर-83.92) को चौथा तथा हांगकांग (स्कोर-83.44) को पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस रिपोर्ट में सबसे निम्न व्यापार नियामक माहौल वाले देशों की सूची में क्रमशः सोमालिया (190वां स्थान), इरिट्रिया (189 वां स्थान), वेनेजुएला (188वां स्थान), दक्षिणी सूडान (187वां स्थान) तथा यमन गणराज्य (186वां स्थान) शामिल हैं।
- वर्ष 2018 हेतु डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत को 100वां स्थान (स्कोर-60.76) प्राप्त हुआ है। गत वर्ष भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था।
- इस सूचकांक में ब्रिक्स देशों में रूस 35वें, चीन 78वें, दक्षिण अफ्रीका 82वें तथा ब्राजील 125वें स्थान पर रहे। ब्रिक्स देशों में व्यापार की सुगमता हेतु पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा सुधार भारत में ही हुआ।
- भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 75वां, नेपाल को 105वां, श्रीलंका को 111वां, पाकिस्तान को 147वां, बांग्लादेश को 177वां तथा अफगानिस्तान को 183वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च रैंकिंग का अर्थ है कि उस विशिष्ट देश की सरकार ने कारोबार करने के लिए अनुकूल विनियामक माहौल उपलब्ध कराया है जबकि निम्न रैंकिंग व्यापार के प्रतिकूल माहौल को दर्शाती है।

भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट-2017

- 13 नवंबर, 2017 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने नई दिल्ली में 'भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट-2017' जारी की।
- इसका उद्देश्य राज्यों में युवाओं के विकास की स्थिति पर करीबी नजर रखना है।
- इस सूचकांक के जरिए लचर और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पहचान आसानी से हो सकेगी।
- इससे राज्यों में युवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले पहलुओं को चिन्हित किया जाएगा और नीति निर्माताओं को जिन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।
- यह सूचकांक एवं रिपोर्ट श्रीपेरुम्बुदूर (तमिलनाडु) स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान द्वारा तैयार की गई है।
- संस्थान ने वर्ष 2010 में इस पहल की शुरूआत की थी जो कि वर्ष 2017 में भारत युवा विकास सूचकांक के तौर पर सामने आई है।
- सूचकांक को तैयार करते समय राष्ट्रीय युवा नीति 2014 (भारत) के अनुसार युवा की परिभाषा और कॉमनवेल्थ की विश्व युवा विकास रिपोर्ट (15-29 वर्ष) के साथ-साथ वैश्विक तुलना के लिए कॉमनवेल्थ सूचकांकों का प्रयोग किया गया है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट-2017

- 2 नवंबर, 2017 को विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2017' (Global Gender Gap Report-2017) जारी की गई।
- इस वर्ष लैंगिक अंतराल सूचकांक में 144 देशों को सूचीबद्ध किया गया है।
- सूची में आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया। इसका कुल स्कोर 0.878 है।
- इसके पश्चात सूची में नॉर्वे (स्कोर-0.830) को दूसरा, फिनलैंड (स्कोर-0.823) को तीसरा, रवांडा (स्कोर-0.822) को चौथा तथा स्वीडन (स्कोर-0.816) को पांचवां स्थान दिया गया है।
- इस सूची में निचले क्रम के 5 देश हैं-यमन (144वां स्थान), पाकिस्तान (143वां स्थान), सीरिया (142वां स्थान), चाड (141वां स्थान) तथा ईरान इस्लामिक गणराज्य (140वां स्थान)।
- भारत को 0.669 स्कोर के साथ सूची में 108वें स्थान पर रखा गया है। गत वर्ष 144 देशों की सूची में भारत को 87वां स्थान दिया गया था।
- सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थिति इस प्रकार रही-
  1. आर्थिक भागीदारी एवं अवसर-139वां स्थान
  2. शैक्षणिक उपलब्धियां-112वां स्थान
  3. स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता-141वां स्थान
  4. राजनीतिक सशक्तिकरण-15वां स्थान
- सूची में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश को 47वां स्थान, चीन को 100वां स्थान, नेपाल को 111वां स्थान, भूटान को 124वां स्थान तथा श्रीलंका को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका 19वें स्थान, रूस 71वें स्थान तथा ब्राजील 90वें स्थान पर रहा।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक चार क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। यह निम्नलिखित हैं-
  1. आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportunity)
  2. शैक्षणिक उपलब्धियां (Educational Attainment)
  3. स्वास्थ्य एवं उत्तर जीविता (Health and Sarvival)
  4. राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment)
- यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है।

GS World
Committed To Excellence

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट-2018

- 14 मार्च, 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) द्वारा छठवीं 'विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट-2018' (World Happiness Report-2018) जारी की गई।
- विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, 2018 की इस सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया है।
- इस सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत उक्त देशों में लोगों की खुशियों के स्तर को मापने हेतु 6 महत्वपूर्ण निर्धारक कारकों (Key Factors) का प्रयोग किया गया है।

ये निर्धारक कारक बिंदुवार निम्नवत हैं-

1. जीडीपी प्रति व्यक्ति आय (GDP Per Capita)
2. स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (Healthy Life Expectancy)
3. सामाजिक स्वतंत्रता (Social Freedom)
4. भ्रष्टाचार का अभाव (Absence of Curruption)
5. सामाजिक अवलंबन (Social Support) तथा
6. उदारता (Generosity)।

- इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुश देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है।
- रिपोर्ट में विश्व के शीर्ष दस देशों में फिनलैंड के बाद क्रमागत रूप से नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्वीडन तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों में जर्मनी 15वें, अमेरिका 18वें, यूनाइटेड किंगडम 19वें, फ्रांस 23वें, सिंगापुर 34वें तथा जापान 54वें स्थान पर है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, इस सूची में भारत 133वें स्थान पर है।
- जबकि गत वर्ष भारत इस सूची में 122वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को 75वां, भूटान को 97वां, नेपाल को 101वां, बांग्लादेश को 115वां तथा श्रीलंका को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस प्रकार भारत इस सूची में अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे है।
- ध्यातव्य है कि शीर्ष 10 देशों में कोई भी एशियाई देश शामिल नहीं है।
- सबसे प्रसन्न एशियाई देशों में इस्राइल को 11वां तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, बुरुंडी विश्व के सबसे प्रसन्न देशों की सूची में अंतिम पायदान पर है। उसका स्थान 156वां है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2012 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अपने नागरिकों की संतुष्टि एवं प्रसन्नता के स्तर को ध्यान में रखते हुए लोक नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरित करना है।

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट-2018

- 11 दिसंबर, 2017 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट-2018' (डब्ल्यूईएसपी-2018) जारी किया गया।
- इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2018 में 7.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का पूर्वानुमान है।
- वर्ष 2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।
- नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में वैश्विक विकास दर का अनुमान 3.0 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2016 के वैश्विक विकास दर (2.4 प्रतिशत) से अधिक है।
- वर्ष 2018 एवं 2019 में इसके 3.0 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है।
- विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2018 एवं 2019 में क्रमशः 2.0 प्रतिशत एवं 1.9 प्रतिशत पूर्वानुमानित है।
- जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2018 एवं 2019 में क्रमशः 4.6 प्रतिशत एवं 4.7 प्रतिशत पूर्वानुमानित है।
- ध्यातव्य है कि 2017 में वैश्विक वृद्धि दर, 2011 के बाद से उच्चतम वृद्धि दर है।
- रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की विकास दर वर्ष 2018 एवं 2019 दोनों ही वर्ष 2.1 प्रतिशत पूर्व अनुमानित है।
- यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 2.0 प्रतिशत एवं 2019 में 1.9 प्रतिशत पूर्वानुमानित है।
- पूर्व एवं दक्षिण एशिया की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 5.8 प्रतिशत एवं 2014 में 5.9 प्रतिशत पूर्वानुमानित है।
- दक्षिण एशिया की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 6.5 प्रतिशत एवं 2019 में 7.0 प्रतिशत पूर्वानुमानित है।

GS World
Committed To Excellence

- रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरूआती आर्थिक सुस्ती और नोटबंदी के दुष्प्रभावों के बावजूद अधिक निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश के अलावा जारी ढांचागत सुधारों के कारण भारत के लिए परिदृश्य काफी सकारात्मक बना हुआ है।
- वर्ष 2018 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.2 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।
- ब्रिक्स देशों में चीन की वृद्धि दर 2018 एवं 2019 में क्रमशः 6.5 एवं 6.3 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।
- रूस की दोनों वर्षों के लिए वृद्धि दर 2008 के लिए क्रमशः 2.0 एवं 1.8 प्रतिशत पूर्वानुमानित है।
- वर्ष 2019 के लिए इन दोनों देशों की वृद्धि दर क्रमशः 2.5 एवं 2.1 प्रतिशत पूर्वानुमानित है।

विश्व निवेश रिपोर्ट

- 7 जून, 2017 को अंकटाड (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) द्वारा 'विश्व निवेश रिपोर्ट (WIR: World Investment Report)-2017 जारी की गई।
- ज्ञातव्य है कि विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन अंकटाड द्वारा वर्ष 1991 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है।
- इस क्रम में वर्ष 2017 की विश्व निवेश रिपोर्ट इसका 27वां संस्करण है।
- विश्व निवेश रिपोर्ट के इस संस्करण का केंद्रीय विषय है–''निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था' (Investment and The Digital Economy)।
- विश्व निवेश रिपोर्ट के प्रत्येक संस्करण में निम्न मुद्दे शामिल किए जाते हैं–
  1. विकास निहितार्थ पर विशेष जोर देने के साथ पिछले वर्ष के दौरान 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (FDI) में रुझान का विश्लेषण।
  2. विश्व में सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय निगमों की रैकिंग
  3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित एक चयनित विषय का गहराई से विश्लेषण।
  4. नीति विश्लेषण और सिफारिशें।
- विश्व निवेश रिपोर्ट–2017 के अनुसार, वर्ष 2015 के 1.76 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में वर्ष 2016 में कुल वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्प्रवाह 2 प्रतिशत कम होकर 1.75 ट्रिलियन डॉलर तथा वर्ष 2018 में 1.85 ट्रिलियन डॉलर रहने की उम्मीद है।
- वर्ष 2016 में विकासशील देशों में एफडीआई अंतर्प्रवाह 14 प्रतिशत कम होकर 646 बिलियन डॉलर रहा।
- वर्ष 2016 में विकासशील एशिया का वैश्विक एफडीआई अंतर्प्रवाह 15 प्रतिशत घटकर 443 बिलियन डॉलर रहा।
- वर्ष 2016 में विकसित देशों में वैश्विक एफडीआई अंतर्प्रवाह 5 प्रतिशत बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर रहा।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) चीन और भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पसंसीदा गंतव्य रहे।
- विश्व निवेश रिपोर्ट–2017 के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाली 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार हैं–
  1. संयुक्त राज्य अमेरिका (391 बिलियन डॉलर)
  2. यूनाइटेड किंगडम (254 बिलियन डॉलर)
  3. चीन (134 बिलियन डॉलर)
  4. हांगकांग चीन (108 बिलियन डॉलर)
  5. नीदरलैंडस (92 बिलियन डॉलर)
- रिपोर्ट के अनुसार भारत 44 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के साथ विश्व का 9वां सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश रहा।
- विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह वाली 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार हैं–
  1. संयुक्त राज्य अमेरिका (299 बिलियन डॉलर)
  2. चीन (183 बिलियन डॉलर)
  3. नीदरलैंड (174 बिलियन डॉलर)
  4. जापान (145 बिलियन डॉलर)
  5. कनाडा (66 बिलियन डॉलर)

नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट

- 9 फरवरी, 2018 को नीति आयोग ने 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' (Healthy States, Progressive India) शीर्षक से एक व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की।

GS World
Committed To Excellence

- इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मोर्चे पर वार्षिक प्रगति तथा एक-दूसरे की तुलना में समग्र प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है।
- यह रिपोर्ट नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव प्रीति सूडान और भारत में विश्व बैंक की कंट्री डायरेक्टर जुनैद कमल अहमद की ओर से संयुक्त रूप से जारी की गयी।
- यह रिपोर्ट स्वास्थ्य क्षेत्र में देश के प्रदर्शन को विविधता तथा जटिलता के आधार पर वार्षिक स्तर पर आंकने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति विकसित करने का प्रयास है।
- नीति आयोग की ओर से यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श तथा विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से तैयार की गयी है।
- रिपोर्ट में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बड़े, छोटे तथा संघ शासित प्रदेशों की तीन श्रेणियों में रखा गया है।
- स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र सूचकांक है जो बड़े राज्यों के लिए तीन विभिन्न श्रेणियों (डोमेन) के तीन संकेतकों (a) स्वास्थ्य परिणाम (70 प्रतिशत) (b) शासन और सूचना तथा (c) प्रमुख आगत और प्रक्रियाओं (18 प्रतिशत) पर आधारित है।
- रिपोर्ट में बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन के मामले में केरल को शीर्ष स्थान दिया गया है।
- इसके पश्चात पंजाब और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- जबकि वार्षिक स्तर पर प्रगति के मामले में झारखंड, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को शीर्ष तीन राज्यों में स्थान मिला है।
- आधार और संदर्भ वर्ष के परिप्रेक्ष्य में नवजात मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर, संपूर्ण टीकाकरण, संस्थागत प्रसव तथा एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी पर निर्भर एचआईवी संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य सुधार के मामले में झारखंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा।
- समग्र प्रदर्शन के मामले में छोटे राज्यों में मिजोरम को पहला स्थान मिला है, जबकि मणिपुर दूसरे स्थान पर है।
- वार्षिक स्तर पर प्रगति के मामले में मणिपुर को प्रथम और गोवा को दूसरा स्थान दिया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में और समग्र प्रदर्शन के साथ ही वार्षिक स्तर पर सबसे अधिक प्रगति के मामले में केंद्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है।
- संस्थागत प्रसव, तपेदिक के सफल उपचार और स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों को सरकारी खजाने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोष में धन के आवंटन के मामले में भी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-2017

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 21 दिसंबर, 2017 को शृंखला का 16वां तथा वर्ष 2017 का दूसरा 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट : दिसंबर, 2017 (Financial Stability Report : December, 2017) जारी किया गया जिसके मुख्य अंश निम्न हैं-
- रिपोर्ट में भौगोलिक-राजनीतिक जोखिम तथा पण्य वस्तुओं (Commodities) की कीमतों में संभावित अस्थिरता की ओर संकेत किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विमुद्रीकरण एवं राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े प्रारंभिक अवरोधों के बाद वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में घरेलू वृद्धि में सुधार हुआ है।
- इसके अलावा कारोबार करने की सुगमता रैंकिंग में सुधार, मूडीज द्वारा भारत की सावरेन रेटिंग में वृद्धि तथा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण घोषणा से आने वाली तिमाहियों में निवेश भावनाओं को प्रोत्साहन मिलना संभावित है।
- भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत अनुमानित है।
- सकल मूल्य वर्धन (GVA) वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के 5.6 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत अनुमानित है।
- सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF), जो वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 34.3 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2016-17 में 29.5 प्रतिशत रह गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग स्थिरता सूचक (BSI) यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम उच्च स्तर पर बने हुए हैं।
- विमुद्रीकरण के बाद भारत में बैंकिंग गतिविधियों में तेजी आई है।
- अक्टूबर, 2016 में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों की कुल संख्या 504 मिलियन थी, जो मार्च, 2017 में बढ़कर 533 मिलियन हो गई।

GS World
Committed To Excellence

- साथ ही इन खातों में जमा राशि 732 बिलियन रुपये से बढ़कर 976 बिलियन रुपये हो गई।
- विमुद्रीकरण प्रभाव से इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में तेजी आई है। इसने लेन-देन के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट आदि की प्रकृति को प्रोत्साहित किया है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की ऋण वृद्धि में मार्च-सितंबर, 2017 के मध्य सुधार दिया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों से इस मामले में पीछे रहे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्च, 2016 से लाभ में कमी दर्ज की गई है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादक अग्रिम (GNPA) अनुपात मार्च-सितंबर, 2017 के मध्य 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सितंबर, 2017 में सकल गैर-निष्पादन अग्रिम में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- निजी क्षेत्र के बैंकों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (17.%) की तुलना में सकल गैर-निष्पादक अग्रिम में 40.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- बैंकिंग क्षेत्र का सकल गैर-निष्पादन अग्रिम (GNPAs) सितंबर, 2017 में सकल अग्रिम (Gross Advances) के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2018 में 10.8 प्रतिशत तथा सितंबर, 2018 में 11.1 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
- विश्व आर्थिक आउटलुक अक्टूबर, 2017 के अनुसार, वैश्विक उत्पादन वृद्धि वर्ष 2017 के 3.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2018 में 3.8 प्रतिशत अनुमानित है।
- अखिल भारतीय आवासीय संपत्ति सूचकांक (RPPI) में वर्ष 2017-18 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.3 प्रतिशत थी।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की साख वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च-सितंबर, 2017 के मध्य 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई।
- दूसरी ओर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च-सितंबर, 2017 के मध्य 11.1 प्रतिशत से 7.8 प्रतिशत तक कम हो गई। बैंकों की जमा वृद्धि में यह कमी सभी बैंक समूहों में देखी गई।
- शुद्ध गैर-निष्पादक अग्रिम (NNPA), कुल शुद्ध अग्रिम के प्रतिशत के रूप में बढ़ा है। यह मार्च-सितंबर, 2017 के मध्य 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शुद्ध गैर-निष्पादक अग्रिम के मामले में उच्च स्तर (7.9%) को दर्ज किया है।

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट-2018

- 14 मार्च, 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) द्वारा छठवीं 'विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट-2018' (World Happiness Report-2018) जारी की गई।
- विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, 2018 की इस सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया है।
- इस सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत उक्त देशों में लोगों की खुशियों के स्तर को मापने हेतु 6 महत्वपूर्ण निर्धारक कारकों (Key Factors) का प्रयोग किया गया है।

ये निर्धारक कारक बिंदुवार निम्नवत हैं-

1. जीडीपी प्रति व्यक्ति आय (GDP Per Capita)
2. स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (Healthy Life Expectancy)
3. सामाजिक स्वतंत्रता (Social Freedom)
4. भ्रष्टाचार का अभाव (Absence of Curruption)
5. सामाजिक अवलंबन (Social Support) तथा
6. उदारता (Generosity)।

- इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुश देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है।
- रिपोर्ट में विश्व के शीर्ष दस देशों में फिनलैंड के बाद क्रमागत रूप से नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्वीडन तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों में जर्मनी 15वें, अमेरिका 18वें, यूनाइटेड किंगडम 19वें, फ्रांस 23वें, सिंगापुर 34वें तथा जापान 54वें स्थान पर है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, इस सूची में भारत 133वें स्थान पर है।
- जबकि गत वर्ष भारत इस सूची में 122वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को 75वां भूटान को 97वां, नेपाल को 101वां, बांग्लादेश को 115वां तथा श्रीलंका को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस प्रकार भारत इस सूची में अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे है।
- ध्यातव्य है कि शीर्ष 10 देशों में कोई भी एशियाई देश शामिल नहीं है।

GS World
Committed To Excellence

1. सबसे प्रसन्न एशियाई देशों में इस्राइल को 11वां तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है।
2. इस रिपोर्ट के अनुसार, बुरुंडी विश्व के सबसे प्रसन्न देशों की सूची में अंतिम पायदान पर है। उसका स्थान 156वां है।
3. गौरतलब है कि वर्ष 2012 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अपने नागरिकों की संतुष्टि एवं प्रसन्नता के स्तर को ध्यान में रखते हुए लोक नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरित करना है।

मानव विकास रिपोर्ट-2016

- 21 मार्च, 2017 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा स्टॉक होम (स्वीडन) में 'मानव विकास रिपोर्ट-2016' (Human Development Report-2016) जारी की गई।
- मानव विकास रिपोर्ट-2016 का शीर्षक 'सभी के लिए मानव विकास' (Human Development for Everyone) है।
- वर्ष 2016 की HDR में 188 देशों को वर्ष 2015 में उनके मानव विकास सूचकांक (HDI) की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है।
- मानव विकास रिपोर्ट-2016 में शामिल 188 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य के आधार पर निम्नलिखित चार भागों में बांटा गया है-
  1. 0.800 और उससे अधिक-अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश।
  2. 0.700 से 0.799 तक-उच्च मानव विकास वाले देश।
  3. 0.550 से 0.699 मध्यम मानव विकास वाले देश।
  4. 0.550 से नीचे निम्न मानव विकास वाले देश।
- HDR-2016 के मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग तालिका में 1 से 51 क्रम संख्या तक के देश 'अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी' में, 52 से 105 क्रम संख्या तक के देश 'उच्च मानव विकास' श्रेणी में, 107 से 147 क्रम संख्या तक के देश, मध्यम मानव विकास श्रेणी में तथा 148 से 188 क्रम संख्या तक के देश 'निम्न मानव विकास' श्रेणी में हैं।
- HDR-2016 में 0.949 मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य के साथ नॉर्वे इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है।
- इसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया एवं स्विट्जरलैंड (HDI मूल्य-0.939), संयुक्त रूप से द्वितीय, जर्मनी (HDI मूल्य-0.926) चौथे तथा डेनमार्क एवं सिंगापुर (HDI मूल्य 0.925) संयुक्त रूप से पांचवे स्थान पर है।
- HDI-2015 में सबसे निचले स्थान (188वें) पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है जिसका HDI मूल्य मात्र 0.352 है।
- इसके पश्चात नाइजर (HDI मूल्य .0353) को 187वां, चाड (HDI मूल्य-0.396) को 186वां, बुर्किना फासो (HDI मूल्य 0.402) को 185वां, बुरुंडी (HDI मूल्य 0.404) को 184वां तथा गिनी (HDI मूल्य-0.414) को 183वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस सूचकांक में भारत 0.624 HDI मूल्य के साथ 131 वें स्थान पर है अर्थात यह 'मध्यम मानव विकास वाले देशो' की श्रेणी में वर्गीकृत है।
- उल्लेखनीय है कि गत वर्ष HDR-2015 में भारत 0.609 HDI मूल्य के साथ भारत का 130 वां स्थान था।
- भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका (0.766 HDI मूल्य के साथ 73वां), चीन (0.738 HDI मूल्य के साथ 90वां), मालदीव (0.738 HDI मूल्य के साथ 105वां स्थान) की स्थिति भारत से बेहतर है।
- जबकि भूटान (0.607 HDI मूल्य के साथ 132वां), बांग्लादेश (0.579 HDI मूल्य के साथ 139वां), नेपाल (0.558 HDI मूल्य के साथ 144वां) तथा पाकिस्तान (0.550 HDI मूल्य के साथ 147वां स्थान) की स्थिति भारत से पीछे है।
- विश्व के अन्य प्रमुख देशों में अमेरिका एवं कनाडा संयुक्त रूप से 10वें, यूनाइटेड किंगडम 16वें, जापान 17वें, फ्रांस 21वें तथा रूस 49वें स्थान पर है।
- ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट हेतु UNDP द्वारा HDI की गणना में नई प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 3 संकेतक शामिल हैं-
  1. जीवन प्रत्याशा सूचकांक (LEI)।
  2. शिक्षा सूचकांक (EI)।
  3. आय सूचकांक (II)।
- मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल-हक तथा 'नोबेल पुरस्कार विजेता' भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था।

GS World
Committed To Excellence

प्रमुख समितियाँ

विनय शील ओबेरॉय समिति

- 7 फरवरी, 2018 को केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं की निगरानी और शीघ्रता के लिए एक 13 सदस्यीय सलाहकार विनय शील ओबेरॉय समिति गठित की है।
- यह समिति पूर्व सचिव विनय शील ओबेरॉय की अध्यक्षता में गठित की गई।
- इस समिति का कार्यकाल अगस्त, 2018 तक होगा।
- समिति पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उपायों का सुझाव देगी।
- इसके अलावा, यह समिति 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति की जांच और स्वतंत्र समीक्षा करेगी।
- समिति "Buy (India) और "Buy and Make" (Indian) सहित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं की समीक्षा करेगा।
- यह समिति 31 मार्च, 2018 तक अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करेगी।

जॉर्ज कुरियन समिति

- 6 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन समिति के अध्यक्ष होंगे।
- समिति के अन्य सदस्यों में आयोग के ही सदस्य सुलेखा कंबरे और मनजीत सिंह राय शामिल हैं।
- आयोग के अतिरिक्त सचिव अजय कुमार इस समिति के सचिव होंगे।
- यह समिति आठ राज्यों जम्मू-कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और लक्षद्वीप में हिंदुओं की संख्या, स्थिति और इनके अन्य पहलुओं से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेगी।
- इसके अलावा समिति अल्पसंख्यक का दर्जा देने की व्यावहारिक और संवैधानिक संभावनाओं पर विचार करेगी।
- समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

बैंकों के विलय पर समिति

- 30 अक्टूबर, 2017 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया है।
- समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्ताव पर गौर करेगी।
- समिति के अन्य सदस्यों में रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।

डॉ. राजीव कुमार समिति

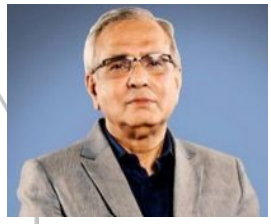

- 4 अक्टूबर, 2017 को केंद्र सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों के उचित प्रबंध के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

समिति के विचार संबंधी विषय निम्नलिखित हैं-

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए वर्तमान व्यवस्था/संस्थागत प्रबंधों का मूल्यांकन।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के जल संसाधनों के अधिकतम प्रबंधन के लिए वर्तमान व्यवस्था/संस्थागत प्रबंधों में अंतरों की पहचान।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी के लिए जल संसाधनों के अधिकतम दोहन के उद्देश्य से नीतिगत सुझाव।
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों के अधिकतम प्रबंधनों के लिए कार्य करने योग्य उपायों की व्याख्या।
5. संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, उनसे संबद्ध कार्यालयों, स्वशासी संस्थाओं की योजनाओं/कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए कार्ययोजना तैयार करना और पूर्वोत्तर राज्यों की योजनाओं को नया रूप देना।

- इसके अलावा समिति पनबिजली, कृषि, जैवविविधता संरक्षण, अपरक्षण, अंतरदेशीय जल परिवहन, वानिकी मछलीपालन और पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में उचित जल प्रबंधन के लाभों को बढ़ाने में सहायता देगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय समन्वय कार्य करेगा।

GS World
Committed To Excellence

- यह समिति कार्य योजना सहित अपनी रिपोर्ट जून, 2018 तक देगी।

पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए समिति

- 2 अक्टूबर, 2017 को अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया।
- राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आयोग का गठन किया।
- आयोग के अन्य सदस्यों में जी.के. बजाज, निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (सदस्य, पदेन), महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त (सदस्य पदेन) तथा संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सचिव) शामिल हैं।

आयोग का कार्य निम्नलिखित है-

1. केंद्रीय सूची में शामिल संदर्भ सहित अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में सम्मिलित जातियों और समुदायों को प्राप्त आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की सीमा का परीक्षण।
2. ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रक्रिया, मानदंड, मानक और मापदंड निर्धारित करना।
3. अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों, समुदायों और उप-जातियों की पहचान करना और उन्हें संबंधित उप-श्रेणियों में विभाजित करना।

- आयोग अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के 12 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

बी.एन. श्रीकृष्ण समिति

- 31 जुलाई, 2017 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की।
- इस समिति में सरकार, शिक्षाविद् एवं उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं।
- इस समिति को डेटा संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों की पहचान एवं अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने के तरीके सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके साथ ही समिति डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे के बारे में भी सुझाव देगी।
- डेटा के संरक्षण से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है।

डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति

- 26 जून, 2017 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।
- समिति के अन्य सदस्यों में शिक्षा तकनीकी क्षेत्र की प्रसिद्ध विद्वान डॉ. वसुधा कामत, केरल के के.जे. अलफोन्से, अमेरिका के प्रिन्सटन विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर रहे डॉ. मंजुल भार्गवा, मध्य प्रदेश के महू स्थित बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राम शंकर कुरील, अमरकंटक स्थित आदिवासी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. टी.वी. काट्टीमानी, उत्तर प्रदेश हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मोहन त्रिपाठी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में फारसी भाषा के प्रोफेसर डॉ. मजहर आसिफ तथा कर्नाटक नवाचार परिषद और कर्नाटक ज्ञान आयोग के पूर्व सदस्य सचिव डॉ. एम.के. श्रीधर शामिल हैं।
- यह समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी।
- एक व्यापक लोकतांत्रिक, प्रक्रिया के तहत, जोकि पिछले 30 महीनों से चल रही थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों एवं अन्य हितधारकों से हजारों सुझाव प्राप्त हुए थे।
- इसके अलावा टीएसआर सुब्रमण्यन समिति ने भी इस पर विस्तार से अपनी सिफारिशें दी थीं।
- वर्तमान में गठित यह समिति इन सभी सुझावों और सिफारिशों पर विचार करेगी।

GS World
Committed To Excellence

'ई-ट्राइब्स इंडिया'

- 27 मार्च, 2018 को जनजातीय मामलों के मंत्री जुआल ओराम ने नई दिल्ली में 'ई-ट्राइब्स इंडिया' नामक वेबसाइट लांच की।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) की वेबसाइट ई-ट्राइब्स में www-tribesindia-com, www-trifed-in तथा रिटेल इंवेंट्री सॉफ्टवेयर और एम-कॉमर्स ऐप शामिल है।
- इस अवसर पर अमेजन, स्नैपडील, पेटीएम तथा जीईएम पर 'ट्राइब्स इंडिया' का बैनर भी लांच किया गया।
- खुदरा व्यापार हेतु ट्राइफेड की पुस्तिका और ट्राइफेड की त्रैमासिक पत्रिका 'ट्राइब्स हाट' का भी विमोचन किया गया।
- ट्राइफेड ने अपने सभी उत्पादों की बिक्री करने तथा एम-कॉमर्स (मोबाइल कॉमर्स) क्षेत्र पर पकड़ हेतु अपनी ई-कॉमर्स (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स) वेबसाइट tribesindia-com विकसित किया है।
- ट्राइफेड के डिजिटल होने से जनजातीय वाणिज्य का विस्तार होगा और बड़े क्षेत्र तक जनजातीय उत्पाद उपलब्ध होंगे जिसका लाभ जनजातीय दस्तकार प्राप्त कर सकेंगे।
- जनजातीय उत्पादों का खुदरा व्यापार देश और विदेश तक फैलेगा।
- ट्राइफेड ने स्नैपडील और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से समझौता किया है, जो जनजातीय उत्पाद अपने ग्राहकों को पेश करेंगे।
- इसके अलावा फ्लिपकार्ट और पेटीएम पर भी जनजातीय भारतीय उत्पाद उपलब्ध होंगे।
- ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के विपणन के अनेक पहलुओं पर काम कर रहा है।
- इन पहलुओं में मोबाइल एनड्रॉयड ऐप्लिकेशन से जनजातीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, प्रदर्शनियों में भागीदारी, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, ट्राइफेड की गतिविधियों पर प्रचार सामग्री की तैयारी शामिल है।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत बहु-राज्य सहकारी सोसायटी है।
- यह संघ अपने 31 खुदरा दुकानों 'ट्राइब्स इंडिया' विभिन्न राज्यों के 37 इंपोरिया और 16 फ्रेंचाइजी दुकानों में जनजातीय उत्पादों को विपणन समर्थन देकर जनजातीय उत्पादों, कला और दस्तकारी के विपणन को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

उद्यमसखी पोर्टल

- 8 मार्च, 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने भारतीय महिला उद्यमियों के लिए उद्यमसखी पोर्टल (www-udyamsakhi.org) शुरू किया।
- इस पोर्टल का शुभारंभ सूक्ष्म, लघु और उद्यम राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया।
- इस पोर्टल के माध्यम से एक ऐसा नेटवर्क बनाने का प्रयास किया गया है। जिसके माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने हेतु कम लागत वाली सेवाओं और उत्पादों हेतु कारोबार के नवीन मॉडल तैयार किए जा सके।
- पोर्टल के माध्यम से महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, निवेशकों से सीधा संपर्क, बाजार सर्वेक्षण सुविधा तथा तकनीकी सहयोग जैसी मदद उपलब्ध कराई गई है।

'इनोवेशन सेल'

- 15 मार्च, 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक 'इनोवेशन सेल' की स्थापना करने का निर्णय किया गया।
- इस सेल की स्थापना भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु नए विचारों को विकसित करने के उद्देश्य से की जाएगी।
- यह निर्णय इसी दिन आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में किया गया, जिससे भारत द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में 6 अंकों के सुधार के पश्चात नवाचार सेल बनाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया।
- वर्ष 2016 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में 66वें स्थान पर रहा जबकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2017 में भारत का स्थान 60वां रहा।
- इनोवेशन सेल का प्रमुख किसी वैज्ञानिक को नियुक्त किया जाएगा।

GS World
Committed To Excellence

- इस सेल में वरिष्ठ अधिकारी और युवा पेशेवरों को भी शामिल किया जाएगा जो नवाचार को प्रोत्साहित करने में नवीन विचारों के साथ आगे आएंगे।

प्रसाद प्लस योजना

- 13 मार्च, 2018 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यटन राज्यमंत्री के.जे. अल्फोंस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहचाने गए तीर्थस्थल या विरासत गंतव्यों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद) प्लस योजना, शुरू की गई है।
- वर्तमान में इस योजना के तहत 25 स्थानों की पहचान की गई है।
- इन स्थलों में अमरावती, श्रीसेलम, तिरुपति, कामाख्या, पटना, गया, द्वारका, सोमनाथ, हजरतबल, कटना, देवघर, गुरुवयूर, ओंकारेश्वर, त्रियंबकेश्वर, पुरी, अमृतसर, अजमेर, कांचीपुरम, वेल्लांकन्ने, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बेलूर शामिल हैं।
- योजना का उद्देश्य तीर्थस्थल या विरासत गंतव्यों के आधारभूत ढांचे का विकास करना है।
- इसमें गंतव्य प्रवेश बिंदुओं का विकास एवं उन्नयन करना शामिल है जिसमें सड़क, रेल और जल परिवहन यात्री टर्मिनल, एटीएम, मुद्रा विनिमय काउंटर, पर्यटन सूचना, व्याख्या केंद्र सहित मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।
- योजनान्तर्गत पर्यावरण हितैषी परिवहन के साथ ध्वनि प्रकाश शो, जल रोमांचकारी क्रीडा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, प्रतीक्षालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, मोबाइल सेवाएं, वाई-फाई, हॉट-स्पॉट आदि का विकास भी शामिल है।

राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम

- 7 मार्च, 2018 को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर.के. सिंह ने भारत में राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने हेतु यह कार्यक्रम पेश किया गया है जिसमें वाहन निर्माता, चार्जिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, फ्लीट ऑपरेटर्स, सेवा प्रदाता आदि शामिल हैं।
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम को लागू करेगी।
- ईईएसएल बड़ी संख्या में बिजली के वाहनों की खरीद करेगा।
- विद्युत वाहन मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह लेंगे।
- ज्ञातव्य है कि ईईएसएल ने वर्ष 2017 में 10,000 ई-वाहनों की खरीद की थी।
- इलेक्ट्रिक कार की प्रति किमी. लागत केवल 85 पैसे है जबकि सामान्य कारों में 6.5 रुपये की लागत पड़ती है।
- इससे पेट्रोलियम आयात को कम करने में मदद मिलेगी।

अटल भूजल योजना

- अप्रैल, 2018 से केंद्र सरकार द्वारा देश में भूजल का संरक्षण तथा इसका स्तर बढ़ाने हेतु महत्वाकांक्षी 'अटल भूजल योजना' शुरू करना प्रस्तावित है।
- इस योजना हेतु 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- यह जानकारी जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदान की।
- इस योजना में विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50:50 प्रतिशत होगी।
- यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत इन प्रदेशों के 78 जिलों, 193 ब्लॉकों और 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार देश के 6584 भूजल ब्लॉकों में से 1034 ब्लॉकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है।
- सामान्यत: इसे 'डार्क जोन' (पानी के संकट की स्थिति) कहा जाता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लक्ष्य में वृद्धि

- 7 फरवरी, 2018 को मंत्रिमंडलीय (सीसीईए) द्वारा 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने को मंजूरी प्रदान की गई।

- इस योजना को महिलाओं मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत

GS World
Committed To Excellence

महिलाओं की ओर से व्यापक समर्थन मिलने और अब तक एलपीजी कनेक्शन से वंचित घरों को इसके दायरे में लाने के उद्देश्य के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।

- केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य में वृद्धि करते वक्त इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को भी दूर कर दिया गया है।
- इस योजना के तहत मुख्यत: सामाजिक, आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण (एसईसीसी) की सूची में शामिल न हो सके वास्तविक निर्धन परिवारों को इसके दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- कैबिनेट ने एसईसीसी के तहत चिह्नित परिवारों के अलावा समस्त एससी या एसटी परिवारों, पीएसएवाई (ग्रामीण) एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों, वनवासियों, अति पिछड़ा वर्गों (एमबीसी), चाय बागानों एवं पूर्व चाय बागानों से जुड़ी जनजातियों, द्वीपों एवं नदियों के समीप निवासरत लोगों को इसके दायरे में लाने हेतु इस योजना का विस्तार करने को मंजूरी प्रदान की है।
- इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक 3 करोड़ कनेक्शन जारी करने का मूल लक्ष्य रखा गया था।
- किन्तु इस योजना के कारगर क्रियान्वयन एवं निगरानी के परिणामस्वरूप सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 3.35 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।
- जिससे मुख्यत: एससी और एसटी समुदाय लाभान्वित हुआ है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत में निर्धन परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी जैसे कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 1 मई, 2016 को शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत प्रारंभ में वित्त वर्ष 2016-17 से शुरू 3 वर्षों की अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।

दर्पण परियोजना

- 21 दिसंबर, 2017 को संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सेवा गुणत्तवा में सुधार, सेवाओं में मूल्यवर्द्धन तथा बैंक सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने हेतु दर्पण (DARPAN-Digital Advancement of Rural Post Office for a New India) परियोजना का शुभारंभ किया।
- इस परियोजना हेतु 1400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

DARPAN
DIGITAL ADVANCEMENT OF RURAL POST OFFICE FOR A NEW INDIA

- आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक शाखा पोस्ट मास्टर (BPM) को कम शक्ति का टेक्नोलॉजी समाधान उपलब्ध कराना है।
- इसके तहत लगभग 1.29 लाख डाकघर शाखाएं सभी राज्यों के ग्रामीण उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार करेंगे।
- आज की तिथि में 43,171 डाकघर की शाखाएं ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दर्पण परियोजना में शामिल हो चुके हैं।
- इस लक्ष्य की पूर्णता अवधि मार्च, 2018 निर्धारित की गई है।
- इस परियोजना के शुरू होने से ग्रामीण आबादी तक डाक विभाग की पहुंच बढ़ेगी तथा सभी वित्तीय प्रेषण, बचत खाता, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और नकद प्रमाण पत्र में वृद्धि होगी।
- परियोजना अंतर्गत स्वचालित बुकिंग की अनुमति तथा खाता योग्य सामग्री की डिलिवरी से मेल संसाधनों में सुधार होगा, खुदरा डाक व्यवसाय से राजस्व में वृद्धि होगी, तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन की उपलब्धता तथा मनरेगा जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए वितरण सहज होगा।
- आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-
  1. ज्यादा ग्राहक संपर्क चैनलों के माध्यम से भारतीय सामान्य जन तक व्यापक पहुंच बनाना।
  2. बेहतर उपभोक्ता सेवा
  3. नए व्यवसायों के माध्यम से विकास
  4. व्यापारिक प्रक्रियाओं एवं समर्थन क्रियाकलापों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षमता बढ़ाना।

न्याय ग्राम परियोजना

- 16 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला रखी।

- इस परियोजना के अंतर्गत न्याय ग्राम परिसर में एक न्यायिक अकादमी स्थापित की जाएगी।
- यह अकादमी उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों की क्षमता विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी।
- इस परिसर में अकादमी के अलावा ऑडिटोरियम और आवास आदि भी बनाए जाएंगे।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप

- 5 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राजधामोहन सिंह ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड -एसएचसी ऐप का शुभारंभ किया।

SOIL HEALTH CARD

Swasth Dhara, Khet Haraa

- उन्होंने विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर, हरियाणा में इस ऐप की शुरूआत की।
- यह ऐप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु विकसित अन्य जियोटैगिंग ऐप के जैसा ही काम करता है।
- इस ऐप में किसान का नाम, आधार कार्ड नम्बर, मोबाइल नम्बर, लिंग, पता, फसल विवरण आदि दर्ज होता है।
- ज्ञातव्य है कि 19 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़, राजस्थान से पूरे देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) योजना की शुरूआत की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों की 12 करोड़ जोतों के मृदा स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्रदान करना है।
- इस कार्ड के माध्यम से किसानों को मिट्टी के पोषक तत्व संबंधी स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।
- इसके अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य व उर्वरता में सुधार करने के संबंध में उचित मात्रा में उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों के संदर्भ में सलाह भी प्राप्त होती है।

उत्तर-पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना

- 23 नवंबर, 2017 को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष ग्रामीण आजीविका, योजना शुरू करने की घोषणा की।
- इस अद्वितीय योजना का नाम 'उत्तर-पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना' है।
- यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित होगी।
- परियोजनान्तर्गत मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासियों और महिलाओं सहित निम्न सामाजिक-आर्थिक समूहों को लाभ मिलेगा।
- यह योजना पूर्वोत्तर के चार राज्यों मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में शुरू की जाएगी।
- दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और गैर-आदिवासी समूहों को सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना शुरू की जाएगी।
- इस परियोजना के तहत 10,000 स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने के साथ ही लगभग 3 लाख गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य 4 उत्तर-पूर्वी राज्यों में ग्रामीण आजीविका में सुधार विशेषकर महिलाओं, बेरोजगार युवकों और सर्वाधिक अलाभान्वितों की आजीविका में सुधार करना है।

सौभाग्य पोर्टल

- 16 नवंबर, 2017 को विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह ने नई दिल्ली में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' के तहत वेब पोर्टल 'सौभाग्य' (http:@@saubhagya.gov.in.) लांच किया।
- सौभाग्य-डैश बोर्ड घरों के बिजलीकरण की निगरानी हेतु एक ऐसा प्लेटफार्म है, जो घरेलू बिजलीकरण की स्थिति (राज्य, जिला, गांवों के क्रम में) लाइव आधार पर प्रगति, राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि तथा बिजलीकरण की मासिक प्रगति के विषय में सूचनाओं का प्रसार करेगा।
- इस पोर्टल में ग्रामीण बिजलीकरण शिविरों के विषय में फीचर है और इस फीचर के अनुरूप बिजली वितरण कंपनियां गांवों/गांवों के समूहों में शिविर लगाकर मौके पर आवेदन करने तथा घरों को बिजली कनेक्शन देने संबंधी आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेंगी।

GS World
Committed To Excellence

- बिजली वितरण कंपनियां/राज्य बिजली विभाग भी समर्पित वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा एकत्रीकरण कर सकेंगे।
  - 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया था।
  - इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक घरों और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है।
  - सरकार का लक्ष्य दिसंबर, 2018 तक देश में 4 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना है।

संकल्प और स्ट्राइव

- 11 अक्टूबर, 2017 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए 'संकल्प' (आजीविका संवर्द्धन के लिए दक्षता हासिल करने और ज्ञान बढ़ाने) तथा 'स्ट्राइव' (औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु दक्षता सुदृढ़ीकरण) योजनाओं को मंजूरी दी।
- दोनों विश्व बैंक समर्थित 6,655 करोड़ रुपये की योजनाएं हैं।
- 4,455 करोड़ रुपये की केंद्रीय प्रायोजित 'संकल्प' योजना में विश्व बैंक द्वारा 3,300 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है।
- जबकि 2,200 करोड़ रुपये की केंद्र प्रायोजित 'स्ट्राइव' योजना में विश्व बैंक से इस योजना की आधी राशि ऋण सहायता के रूप में दी जाएगी।

- इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य दक्षता विकास, प्रशिक्षण के दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों के मामलों में गुणवत्ता एवं बाजार की सार्थकता के दृष्टिगत संस्थागत सुधार लाना है।
- 'संकल्प' और 'स्ट्राइव' योजनाएं निष्कर्ष आधारित हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति को आदानों के साथ परिणामों से जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना

- 2 अक्टूबर, 2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना का अनावरण किया गया।
- पंद्रह वर्षीय इस कार्ययोजना की अवधि 2017 से 2031 तक है।
- तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना में पहली बार वन्य जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को मान्यता दी गई।
- योजना का अनावरण ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम (जीडब्ल्यूपी) सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर किया गया।
- जीडब्ल्यूपी पहल को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
- जीडब्ल्यूपी सम्मेलन से भारत को वन्यजीव पर्यावास प्रबंधन तथा मानव वन्यजीव संघर्ष स्थितियों को कम करने के बेहतर तौर तरीकों की जानकारी होगी।
- पंद्रह वर्षीय कार्ययोजना की पहल फरवरी, 2016 में की गई थी।
- योजना के प्रारूप को मंत्रालय के पूर्व सचिव जे.सी. काला की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय समिति ने तैयार किया था।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र पर्याप्त और निरंतर धन उपलब्ध कराएगा।
- साथ ही कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का भी उपयोग होगा।

पेंसिल पोर्टल

- 26 सितंबर, 2017 को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित बालश्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- इसका आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया।
- इस अवसर पर गृहमंत्री ने बाल मजदूरी निषेध पोर्टल के कारगर कार्यान्वयन हेतु मंच (पेंसिल) का शुभारंभ किया।
- 'पेंसिल' श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है।

GS World
Committed To Excellence

- जिसका लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों, जिला स्तरीय प्रशासन, सिविल सोसाइटी और आम लोगों को शामिल कर बालश्रमिक मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करना है।
- इस अवसर पर ही गृहमंत्री ने बाल मजदूरी के विरुद्ध कानूनी फ्रेमवर्क लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं भी जारी की।
- मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य प्रशिक्षकों, अधिवक्ताओं और निगरानी एजेंसियों हेतु एक मार्गदर्शक तैयार करना है जिससे बाल मजदूरी को पूर्णतः समाप्त किया जा सके और जोखिम पूर्ण श्रम से किशोरी की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- इसका अंतिम उद्देश्य भारत को बाल मजदूरी से मुक्त करना है।

इस पोर्टल के निम्नलिखित घटक हैं:-

(1) चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम

(2) शिकायत प्रकोष्ठ

(3) राज्य सरकार

(4) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और

(5) परस्पर सहयोग।

- बाल श्रम (निषेध और संशोधन) अधिनियम, 2016, 1 सितंबर, 2016 से देश में लागू है।
- इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना समग्र और पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया गया है।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना वर्ष 1988 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य बालश्रम के सभी रूपों से बच्चों को बाहर निकालना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना था।
- 'श्रमक्षेत्र' समवर्ती सूची में शामिल है।

'दिव्यांग सारथी' मोबाइल ऐप

- 26 सितंबर, 2017 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 'दिव्यांग सारथी' मोबाइल ऐप के बीटा संस्करण का उद्घाटन किया।
- इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित विभिन्न उपयोगी जानकारियों जैसे विभिन्न नियमों दिशा-निर्देशों, योजनाओं, रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में दिव्यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराना है।
- यह ऐप यूनिर्सल एक्सेस के यूएनसीआरपीडी के सिद्धांतों और दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि सभी जानकारियों को एक सरल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- यह ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर, 2015 को शुरू किए गए 'सुगम्य भारत अभियान' के आईसीटी घटक का एक अभिन्न हिस्सा है।

सुगम्य भारत अभियान
सुगम्य भारत – सशक्त भारत

- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं, जो कुल जनसंख्या के 2.2 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई स्कीम संपदा (Scheme For Agro- Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) के पुनः नामकरण 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' (PMKSY) का अनुमोदन किया।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।

- यह 14वें वित्त आयोग के समाप्ति वर्ष 2016-20 अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इस योजना से वर्ष 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपये के निवेश से प्राप्त शक्ति से 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होने की आशा है।
- सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं-
  1. खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए सरकार ने भारत में निर्मित अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के बारे में ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को अनुमति दी है।
  2. सरकार ने अभिहित खाद्य पार्कों और इनमें स्थित कृषि-प्रसंस्करण यूनिटों को रियायती ब्याज दर पर वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये का विशेष कोष भी स्थापित किया है।

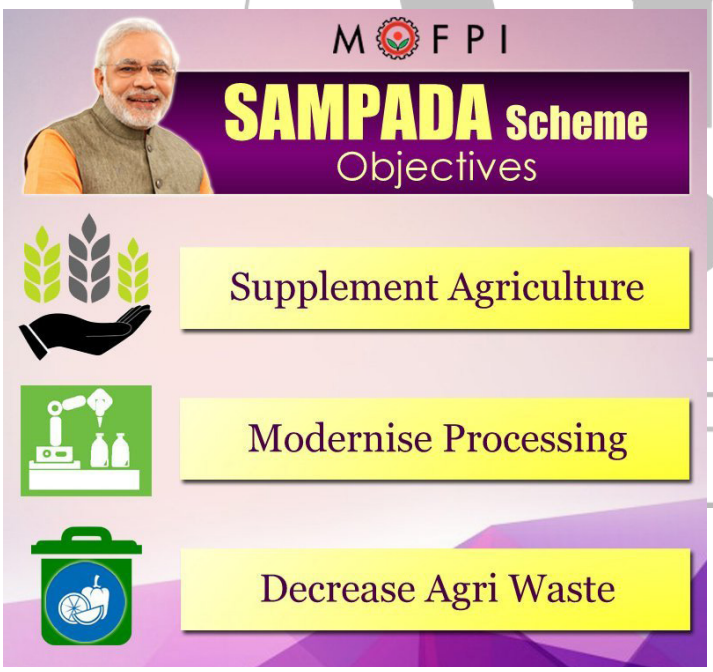

- इस योजना के कार्यान्वयन से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कार्यक्षमता आपूर्ति प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा।
- यह देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायक होगा।

जियो पारसी

- 28 जुलाई, 2017 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में 'जियो पारसी पब्लिसिटी फेज-2' का शुभारंभ किया।
- इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत हस्तक्षेप के द्वारा पारसियों की जनसंख्या में वृद्धि करना है।
- इस योजनान्तर्गत मंत्रालय द्वारा परामर्श एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है।
- जियो पारसी पब्लिसिटी फेज-1 की शुरूआत वर्ष 2013 में हुई थी।
- भारत में पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने हेतु अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 'जियो पारसी योजना' संचालित की जा रही है।

आरंभ

- 24 जुलाई, 2017 को केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायतीराज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की उपमहानिदेशक (नीति) देबोरा ग्रीनफील्ड ने सड़क रख-रखाव हेतु मोबाइल ऐप 'आरंभ' का शुभारंभ किया।
- इसके अलावा उन्होंने निम्नलिखित प्रकाशनों यथा संकल्पना नोट और मार्गदर्शन नोट 'ग्रामीण सड़क के रख-रखाव हेतु निधि एकत्रित करना' का भी शुभारंभ किया।
- इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव प्रबंधन को सुगम बनाया जाएगा।
- भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण कर सभी योग्य बस्तियों को जोड़ना है।
- इस मोबाइल फोन ऐप का लक्ष्य सड़क सूची बनाने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित मानचित्रण का उपयोग, स्थिति सर्वेक्षण और उत्पादन लागत अनुमान और वार्षिक सड़क रख-रखाव योजनाओं की तैयारी और निगरानी हेतु अन्य प्रासंगिक डेटा जुटाना है।

गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र

- मुख्तार अब्बास नकवी ने देश के 100 जिलों में 'गरीब नवाज कौशल विकास केंद्रों' की स्थापना की घोषणा की ।
- इस केंद्र में लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं का रोजगार पूरक कौशल विकास होगा।

- यह केंद्र आगामी 6 माह में हैदराबाद, नोएडा, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, औरंगाबाद, भोपाल, इंदौर, इलाहाबाद, मैसूर, चेन्नई, गोवा, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, किशनगंज, देहरादून, शाहजहांपुर, रामपुर, रांची, गिरीडीह, मेवात, तिजारा, पानीपत, दिल्ली, ऊधमसिंह नगर, अमृतसर, चंडीगढ़, मुंबई आदि स्थानों पर शुरू किया जाएगा।
- केंद्र सरकार पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर 15 अक्टूबर को शिक्षा का एक बड़ा अभियान 'तहरीके तालीम' शुरू करेगी।

www.studymasterofficial.com

स्वयं, स्वयंप्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटिरी

- 9 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में देश में ई-शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु तीन डिजिटल पहलों स्वयं, स्वयंप्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटिरी की शुरूआत की।
- इस कार्यक्रम में केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और भारतीय प्रबंधन संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों ने भाग लिया।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार इन पहलों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, 2015-16 के 24.5 से बढ़कर 2020 तक 30 हो जाएगी।
- इन पाठ्यक्रमों को आईआईटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और जे एन यू जैसे संस्थानों के 1000 से ज्यादा विशेषज्ञ संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है।
- स्वयं-यह कक्षा IX से स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए कक्षाओं में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को होस्ट करेगा, जिसे किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किसी के भी द्वारा पहुंचाया जा सकता है।
- यह उन लोगों को जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और ऐसे पेशेवर जो अपने ज्ञान को अपग्रेड करना चाहते हैं, लक्षित करेगा।
- स्वयंप्रभा-यह जीसैट-15 उपग्रह का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का 24×7 प्रसारण हेतु समर्पित 32 डीटीएच चैनलों का मंच है।
- नेशनल एकेडमिक डिपॉजीटरी-यह प्रमाण पत्र के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा।
- सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव हैं और नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
- भारत में विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को क्लियर करने के लिए क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम होंगे।

भारत को जानें कार्यक्रम

- 17 जून, 2017 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 'भारत को जानें' कार्यक्रम ऑनलाइन वेब पोर्टल (KIP online web Portal) का उद्घाटन किया गया।
- यह विदेशों में निवासरत भारतीय युवाओं (18-30 वर्ष के आयु) के लिए तीन सप्ताह का अधिमुखीकरण कार्यक्रम है।
- जिसका उद्देश्य-प्रतिभागियों के मध्य भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता का सृजन करना और उनको देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों यथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में हासिल उपलब्धि की प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करना है।
- ध्यातव्य है कि यह कार्यक्रम, विदेश मंत्रालय के अधीन प्रवासी भारतीय विभाग द्वारा 2003 से अस्तित्व में है।

टेली-लॉ प्रणाली

- 11 जून, 2017 को समाज के उपेक्षित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को कानूनी सहायता सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा टेली-लॉ प्रणाली का शुभारंभ किया गया।

- इस कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेंगे।
- इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पूरे देश में पंचायत स्तर पर संचालित सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) का उपयोग किया जाएगा।
- प्रथम चरण के दौरान टेली-लॉ कार्यक्रम प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में 500 सामान्य सेवा केंद्रों में संचालित होगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत टेली-लॉ नामक पोर्टल शुरू किया जाएगा जो समस्त कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

- यह पोर्टल प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्म की सहायता से नागरिकों को कानून सेवा प्रदाताओं के साथ संबद्ध करेगा।
- टेली लॉ के माध्यम से लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों पर वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके अलावा लॉ स्कूल क्लिनिकों, जिला विधि सेवा प्राधिकारियों, स्वयंसेवी सेवा प्रदाताओं और कानूनी सहायता एवं अधिकारिता के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को भी सीएससी के साथ संबद्ध किया जाएगा।

www.studymasterofficial.com

- राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्यों की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा।
- यह पैनल आवेदकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करेगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सामान्य सेवा केंद्र पर पैरा लीगल वालंटियर की नियुक्ति की जाएगी जो ग्रामीण नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा और कानूनी मुद्दे को समझने में उनकी मदद करेगा।
- इन चयनित वालंटियरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिससे कि वह अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें।
- इस परियोजना के अंतर्गत झारखंड के तीन जिलों के दस सामान्य सेवा केंद्रों और राजस्थान के 11 जिलों के 500 सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है।
- इसके तहत राजस्थान में 500 स्वयंसेवी विधि विशेषज्ञों को सामाजिक न्याय कानूनों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
- इस कार्यक्रम के मध्यम से 1000 महिला अर्द्ध-विधिक स्वयं सेवकों के क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।

साथ कार्यक्रम

- 10 जून, 2017 को नीति आयोग द्वारा सहकारी संघवाद के एजेंडे को बढ़ावा देने हेतु 'साथ' (SATH- Sustainable Action for transforming Human Capital) मानव पूंजी के रूपांतरण हेतु स्थायी कार्यक्रम नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में परिवर्तन की शुरूआत करना है।
- यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों द्वारा नीति आयोग से अपेक्षित तकनीकी सहायता की आवश्यकता की पूर्ति करेगा।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों हेतु तीन भविष्य के रोल मॉडल राज्यों को चिह्नित करना और निर्माण करना है।
- नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने हेतु राज्यों की मशीनरी के साथ सहयोग प्रदान कर हस्तक्षेप का सुदृढ़ रोडमैप बनाएगा, कार्यक्रम प्रशासन संरचना का ढांचा विकसित करेगा और निगरानी एवं अन्वेषण व्यवस्था स्थापित करेगा।
- इसके तहत संस्थागत उपायों के माध्यम से राज्यों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह कार्यक्रम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित मैकिन्से एंड कंपनी और आईपीई ग्लोबल कांसोर्टियम के साथ नीति आयोग द्वारा लागू किया जाएगा।
- तीन मॉडल राज्यों के चयन हेतु नीति आयोग ने तीन चरण की प्रक्रिया को परिभाषित किया सरोकार की अभिव्यक्ति, राज्यों के प्रस्तुतीकरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के प्रति वचनबद्धता का मूल्यांकन।
- नीति आयोग द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को आमंत्रित किया गया था।
- जिनमें से 14 राज्यों ने अपने परियोजना प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष प्रस्तुत किए।
- इन 14 राज्यों में 5 को चयनित किया गया।
- इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा जहां यह कार्यक्रम लागू होगा।
- राज्यों का अंतिम चयन विभिन्न स्वास्थ्य मानदंडों यथा प्रसूति मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मलेरिया और अन्य घटनाओं पर संभावित प्रभावों का निर्धारण आदि के आधार पर किया जाएगा।

ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना

- 5 जून, 2017 को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना क्रियान्वित करने की घोषणा की।
- इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के माध्यम से आंध्र प्रदेश के 7 जिलों की ग्राम पंचायतों में 10 लाख परंपरागत स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगाएगी।

- प्रथम चरण में गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर जिलों की ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइट लगाई जाएगी।
- इस परियोजना से ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष कुल मिलाकर लगभग 147 मिलियन यूनिट बिजली की बचत करने में मदद मिलेगी।

- इससे 12 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) की रोकथाम संभव हो पाएगी।
- इस परियोजना पर आने वाली कुल पूंजीगत लागत का वित्त पोषण एजेंसे फ्रांकेइसे डे डेवलपमेंट (AFD) नामक फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- इस परियोजना के तहत ईईएसएल अगले 10 वर्षों तक इन ग्राम पंचायतों में समस्त वार्षिक रख-रखाव और वारंटी प्रतिस्थापन का कार्य करेगी।
- उल्लेखनीय है कि देश के 21 राज्यों में 23 लाख से भी ज्यादा परंपरागत स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलइडी स्ट्रीट लाइट सरकार द्वारा लगाई गयी है जिससे बिजली की बचत सुनिश्चित हुई है।

सेवा एप

- 23 मई, 2017 को केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल द्वारा सरल ईंधन वितरण ऐप्लिकेशन (SEVA: SaralEindhanVitaran Application) का शुभारंभ किया गया।
- यह ऐप बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया है।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं से संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ कोयला प्रेषण में पारदर्शिता लाने और सरकार को अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी बनाना है।
- इस ऐप से कोल इंडिया लिमिटेड देश के आठ राज्यों में स्थित 118 बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति की निगरानी करेगा।
- इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा भी होगा।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

- 21 जुलाई, 2017 को केंद्रीय वित्त, रक्षा, और कारपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' (PMVVY) का औपचारिक शुभारंभ किया।
- यह भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।
- यह योजना 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को इस योजना का संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया है।
- इस योजना को एलआईसी के माध्यम से ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी खरीदा जा सकता है।

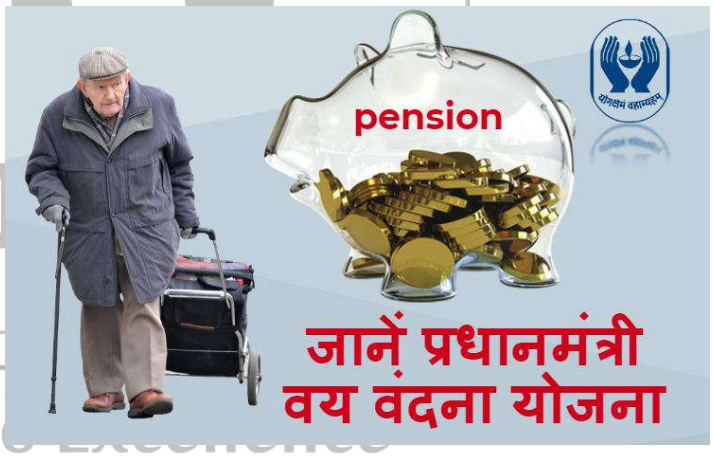

इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-

1. यह योजना 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रभावी के समतुल्य) का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है।
2. योजना की खरीदारी के समय पेंशन भोगी द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है।
3. इस योजना को सेवाकर/जीएसटी से छूट दी गई है।

4. 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनधारक के जीवित रहने पर योजना के क्रय मूल्य के साथ पेंशन की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा।
5. तीन पॉलिसी वर्ष (नगदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए) के अंत में क्रय मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी। ऋण के ब्याज का भुगतान पेंशन की किस्तों से किया जाएगा।
6. इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी गंभीर टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है।
   - ऐसे समय पूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी।
7. 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

- 8 मार्च, 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ झुंझुनू, राजस्थान में किया।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार की शुरूआत भी की।
- यह अभियान देश के 640 जिलों में संचालित होगा।
- वर्तमान में यह अभियान देश के 161 जिलों में संचालित है।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान जनवरी, 2015 में शुरू किया गया था।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लोगो प्रतियोगिता और राष्ट्रीय पोषण मिशन लोगो प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया।
- इस अभियान की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक फोटो जर्नी बुक जारी किया जिसमें विभिन्न जिलों द्वारा उठाए गए कदमों (नए व अनोखे) की तस्वीरें शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा तथा कन्या भ्रुण हत्या निरोधक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उत्कृष्ट प्रदर्शनी करने वाले 10 जिलों को पुरस्कृत भी किया।
- इन जिलों को निम्न श्रेणियों में उनके योगदान हेतु सम्मानित किया गया है।
- प्रभावी समुदाय भागीदारी श्रेणी में 6 जिले रायगढ़ (छत्तीसगढ़), सीकर (राजस्थान), बीजापुर (कर्नाटक), उत्तरी सिक्किम (सिक्किम), तरनतारन (पंजाब), हैदराबाद (तेलंगाना) सम्मानित किए गए।
- पीसी और पीएनडीटी अधिनियमों के कार्यान्वयन श्रेणी में दो जिलों सोनीपत (हरियाणा) और अहमदाबाद (गुजरात) को पुरस्कृत किया गया।

www.studymasterofficial.com

- बालिकाओं की शिक्षा श्रेणी में दो जिले झुंझुनू (राजस्थान) और उधमपुर (जम्मू और कश्मीर) को सम्मानित किया गया।
- बेटी बेटी पढ़ाओ योजना, के तहत कुल 1132.5 करोड़ रुपए की धनराशि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए निर्धारित की गई है।
- इस कार्यक्रम का प्रारंभिक फोकस उन जिलों पर था जिनका औसत शिशु लिंग दर (सीएसआर) के सदर्भ में राष्ट्रीय औसत से कम था या ऐसे जिले जिनका प्रदर्शन राज्यों के औसत शिशु लिंग दर से कम था।
- वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 926 हो गया है।
- ज्ञातव्य है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वृंदावन, मथुरा में 1000 विधवा आश्रम खोले गए हैं और वाराणसी में भी ऐसा ही एक आश्रम बनाया जा रहा है।
- दुष्कर्म से जुड़े मामलों की त्वरित जांच हेतु चंडीगढ़ में फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।
- केंद्र सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं हेतु 200 साक्षी केंद्र खोले गए हैं।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) का गठन 9046.17 करोड़ रुपए राशि से किया गया है।
- यह मिशन देश में पोषण के स्तर को युद्धस्तर पर बढ़ाने का एक समग्र प्रस्ताव है जिसमें कुपोषण को दूर करने में योगदान कर रही विभिन्न योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
- इस मिशन का लक्ष्य बच्चों के बौनापन, आवश्यकता से कम पोषण, खून की कमी, और जन्म के समय बच्चों के कम वजन को 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक लाना है।
- इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

गोबर-धन योजना

- सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत बजट 2018-19 में गोबर-धन योजना की आज घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 आकांक्षायुक्त जिलों की पहचान की है।

- इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय तक पहुंच आदि में निवेश करके निश्चित समयावधि में विकास की गति को तेज किया जाएगा. मंत्री ने उम्मीद जताई कि ये 115 जिले विकास के मॉडल साबित होंगे

एक ऐसा संस्थान जो कि अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

You Deserve the Best...

!! संस्थान द्वारा चलाये जा रहे कोर्स !!

- सामान्य अध्ययन प्रारम्भिक परीक्षा कार्यक्रम
- सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा कार्यक्रम
- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स
- सी-सैट कक्षा कार्यक्रम
- निबन्ध कक्षा कार्यक्रम

!! हमारे कक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ!!

- नियमित कक्षा टेस्ट
- छात्रों के द्वारा परिचर्चा (Debate) कार्यक्रम
- व्यक्तित्व विकास हेतु विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- उत्तर लेखन संवर्द्धन कार्यक्रम
- अद्यतन एवं गुणवत्ता पूर्ण अध्ययन सामग्री

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

You Deserve the Best...

IAS GS WORLD PCS

Committed To Excellence

सूचकांक, रिपोर्ट्स, योजनाएं एवं समितियाँ
(महत्वपूर्ण तथ्य)

मई 2017 से मार्च 2018

IAS GS WORLD PCS

Committed To Excellence